भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

द्विपक्षीय समझौतों से व्यापार को और बढ़ावा

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- विदेशी व्यापार में मजबूत वृद्धि दर्ज की गई. अप्रैल-जून 2026 में निर्यात और आयात दोनों में अच्छी बढ़ोतरी हुई.
- भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौते और अन्य द्विपक्षीय समझौतों से व्यापार को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
- विदेशी निवेश में रिकवरी देखी गई. अप्रैल-मई में सकल और शुद्ध FDI पिछले साल से ज्यादा रहा. विदेशी पोर्टफोलियो निवेश भी जून में सकारात्मक हो गया.
- मुद्रास्फीति पर नियंत्रण: जून में खुदरा महंगाई में मामूली बढ़ोतरी हुई, लेकिन मुख्य मुद्रास्फीति निम्न स्तर पर बनी रही.

नई दिल्ली, 23 जुलाई. वैश्विक स्तर पर आर्थिक अनिश्चितता और चुनौतियों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हुआ है. आरबीआई के जुलाई मासिक बुलेटिन में कहा गया है कि जून तक आर्थिक गतिविधियां तेज रफ्तार से चल रही हैं.

औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के संकेतक मजबूत बने हुए हैं, जबकि मजबूत घरेलू मांग ने बाहरी दबावों का सफलतापूर्वक सामना किया है.

आरबीआई ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था अभी भी आपूर्ति श्रृंखला के व्यवधान, भू-राजनीतिक तनाव और बिखरे व्यापारिक संबंधों जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है, लेकिन भारत की मजबूत घरेलू अर्थव्यवस्था इन चुनौतियों से निपटने में सक्षम साबित हो रही है.

बुलेटिन में यह भी उल्लेख किया गया कि मार्च 2026 के अंत तक भारत के प्रमुख बाह्य क्षेत्रीय जोखिम संकेतक मजबूत और संतुलित स्थिति में रहे.

कच्चे तेल के दबाव में रुपया टूटा

मुंबई, 23 जुलाई. कच्चे तेल के दबाव में बुधवार को डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट रही और यह दो महीने से अधिक के निचले स्तर पर बंद हुआ. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में रुपया आज 28 पैसे टूट गया और कारोबार की समाप्ति पर एक डॉलर 96.53 रुपये का बोला गया. यह 20 मई के बाद रुपया का निचला बंद स्तर है. बीच कारोबार में यह 96.60 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया था. पिछले कारोबारी दिवस पर भारतीय मुद्रा 11 पैसे की मजबूती के साथ 96.25 रुपये प्रति डॉलर पर रही थी. रुपये की शुरुआत आज नौ पैसे की गिरावट के साथ 96.36 रुपये प्रति डॉलर पर हुई और कुछ ही देर में यह 96.26 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया. हालांकि इसके बाद इसका ग्राफ लगातार नीचे की तरफ उतरता गया.

अडानी पावर को 4,867 करोड़ का मुनाफा

सालाना आधार पर 47 प्रतिशत ऊपर

पहली तिमाही में ईंधन की लागत 30 % बढ़कर 9,513 करोड़ रुपये हो गयी

मुंबई, 23 जुलाई. अडानी पावर को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 4,867 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ, जो सालाना आधार पर 47 प्रतिशत ऊपर है. कंपनी के निदेशक मंडल की बुधवार को हुई बैठक के बाद वित्तीय परिणामों की घोषणा की गयी.

अप्रैल-जून तिमाही के दौरान कंपनी का सतत परिचालन राजस्व 28 प्रतिशत बढ़कर 17,550 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इस दौरान सतत परिचालन लाभ 6,983 करोड़ रुपये हो गया. इसमें 22 फीसदी की वृद्धि हुई है. अडानी पावर ने बताया कि पहली तिमाही में ईंधन की लागत 30 प्रतिशत बढ़कर 9,513 करोड़ रुपये हो गयी. पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में यह 7,309 करोड़ रुपये रही थी. वित्तीय परिणामों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए अडानी पावर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.बी. ख्यालिया ने कहा कि एक बार फिर सतत आधार पर रिकॉर्ड परिचालन लाभ अर्जित किया है. यह उसके सक्षम पोर्टफोलियो और परिचालन की उत्कृष्टता को रेखांकित करता है. उसके पोर्टफोलियो का आकार बढ़कर 45 गीगावाट पर पहुंच गया है.

> कंपनी की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साल गर्मी के मौसम में तापमान सामान्य से अधिक रहने और लंबे समय तक लू चलने के कारण देश में बिजली की मांग मई में रिकॉर्ड 270 .8 गीगावाट दर्ज की गयी. तिमाही में बिजली की खपत एक साल पहले के 8 .4 प्रतिशत बढ़कर 485 .4 अरब यूनिट पर पहुंच गयी.

अजियो ब्यूटी की 1,500 ब्रांड्स के साथ शुरुआत

मुंबई, 23 जुलाई. अजियो पर पहले से उपलब्ध ब्यूटी प्रोडक्ट्स का दायरा बड़ा करते हुए रिलायंस रिटेल ने बुधवार को अजियो ब्यूटी की शुरुआत की घोषणा की.

अजियो ब्यूटी पर ग्राहकों को 1,500 से अधिक भारतीय और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड्स के स्किनकेयर, मेकअप, हेयरकेयर, फ्रेगरेंस और पर्सनल केयर उत्पाद एक ही जगह मिलेंगे. रिलायंस रिटेल ने बुधवार को बताया कि अजियो ब्यूटी पर स्किनकेयर, मेकअप, हेयरकेयर, फ्रेगरेंस, बाथ एंड बॉडी, पर्सनल केयर और ब्यूटी एक्सेसरीज की विस्तृत रेंज उपलब्ध होगी. इसमें रोजमर्रा के किफायती उत्पादों से लेकर प्रीमियम और लग्जरी ब्रांड्स तक शामिल होंगे.

कंपनी के मुताबिक, इन उत्पादों की डिलीवरी देशभर के 19,000 से अधिक पिन कोड पर की जायेगी. चुनिंदा शहरों में अजियो रश के जरिये तेज डिलीवरी की सुविधा भी मिलेगी. इस नये प्लेटफॉर्म के लिए रिलायंस रिटेल ने अपने ओम्नीचैनल ब्यूटी प्लेटफॉर्म टीरा की विशेषज्ञता को अजियो की डिजिटल पहुंच के साथ जोड़ा है.

स्पाइसजेट ने डैम्प लीज पर तीन विमान बेड़े में शामिल किये

नई दिल्ली, 23 जुलाई. निजी विमान सेवा कंपनी स्पाइसजेट ने अपने बेड़े में तीन एयरबस ए320 विमान डैम्प लीज पर शामिल करने की घोषणा की है. वित्तीय संकट से जूझ रही विमान सेवा कंपनी ने गुरुवार को बताया कि तीन अतिरिक्त विमान बेड़े में आने से नेटवर्क विस्तार और बढ़ती यात्री मांग की पूर्ति में मदद मिलेगी. डैम्प लीज के तहत विमान के साथ पायलट भी विमान लीज पर देने वाली कंपनी के ही होते हैं. साथ ही विमान के रखरखाव की जिम्मेदारी भी उसी कंपनी की होती है. वहीं केबिन क्रू विमान लीज पर लेने वाली कंपनी के होते हैं. स्पाइसजेट के अनुसार, तीनों विमान भारत पहुंच चुके हैं और इस सप्ताह के अंत तक उनका व्यावसायिक परिचालन शुरू हो जायेगा.

एशिया संकट से हिंदुस्तान पेट्रोलियम को नुकसान

कच्चे तेल की कीमतों में आया तेज उछाल

नई दिल्ली, 23 जुलाई. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पश्चिम एशिया संकट के कारण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर 17,446 करोड़ रुपये का कर पूर्व नुकसान हुआ है.

हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने बुधवार को निदेशक मंडल की बैठक के बाद वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की. इसमें बताया गया है कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में कंपनी की कुल आय 1,46,407 करोड़ रुपये रही. इस दौरान उसका कुल व्यय बढ़कर 1,63,853 करोड़ रुपये हो गया. इस प्रकार कर पूर्व नुकसान 17,446 करोड़ रुपये हुआ. कंपनी पर 5,920 करोड़ रुपये की कर की देनदारी टाल दी गयी है जिससे उसका शुद्ध नुकसान 11,526 करोड़ रुपये रह गया. कंपनी की बैलेंसशीट से स्पष्ट है कि नुकसान का मूल कारण पश्चिम एशिया संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल है.

> वहीं, भंडार में तैयार माल की कीमत बढ़ने से कंपनी को 4,402 करोड़ रुपये का लाभ हुआ जबकि केंद्र सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क घटाने से इस मद में उसका खर्च एक साल पहले के 9,368 करोड़ रुपये से कम होकर 4,641 करोड़ रुपये रहा गया . कंपनी ने बताया कि उसकी रिफाइनरियों ने तिमाही में 65 .2 लाख टन कच्चे तेल का शोधन किया जो उसकी क्षमता का 107 प्रतिशत है .

आध्यात्मिक यात्रा 11 अगस्त 2026 को सोलापुर से प्रारंभ

आईआरसीटीसी की सोलापुर से भारत गौरव पर्यटक ट्रेन द्वारा सप्त ज्योतिर्लिंग श्रावण स्पेशल यात्रा

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम, रेल मंत्रालय के अधीन एक नवरत्न सार्वजनिक उपक्रम, ने भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के अंतर्गत सप्त ज्योतिर्लिंग श्रावण स्पेशल यात्रा के संचालन की घोषणा की है.

यह विशेष आध्यात्मिक यात्रा 11 अगस्त 2026 को सोलापुर से प्रारंभ होगी और श्रद्धालुओं को देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों एवं पवित्र तीर्थस्थलों के दर्शन का अवसर प्रदान करेगी. 13 रातें एवं 14 दिनों की यह विशेष यात्रा श्रावण मास के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए तैयार की गई है, जिसमें आध्यात्मिकता, सुविधा एवं सुरक्षित यात्रा का समन्वय किया गया है. इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु द्वारकाधीश मंदिर (द्वारका), सोमनाथ ज्योतिर्लिंग (वेरावल), महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग (उज्जैन), त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग (नासिक), घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग (छत्रपति संभाजीनगर के निकट) तथा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग (मार्कापुर) के दर्शन कर सकेंगे. इस अवसर पर श्री गौरव झा, समूह महाप्रबंधक, आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, ने बताया कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेन में लगभग 750 यात्रियों के लिए व्यवस्था की गई है. यात्रियों की सुविधा के लिए इकोनॉमी स्लीपर , स्टैंडर्ड 3एसी तथा कम्फर्ट 2एसी श्रेणियों में यात्रा का विकल्प उपलब्ध होगा.

> डॉ. ए. के. सिंह, प्रवक्ता, आईआरसीटीसी पश्चिम क्षेत्र, ने कहा कि यह पहल देश में आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ श्रद्धालुओं को सुरक्षित, किफायती एवं सुविधाजनक यात्रा अनुभव प्रदान करेगी. उन्होंने कहा कि भारत गौरव पर्यटक ट्रेनें देश की समृद्ध धार्मिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत को जन-जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं.

इंफोसिस का तिमाही मुनाफा 7,769 करोड

बेंगलुरु, 23 जुलाई. सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंफोसिस को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में समेकित आधार पर 7,769 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ हुआ है जो पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही की तुलना में 12.2 प्रतिशत अधिक है.

इंफोसिस के निदेशकमंडल की दो दिन चली बैठक के बाद गुरुवार को वित्तीय परिणामों को मंजूरी प्रदान की गयी. कंपनी ने बताया कि अप्रैल-जून 2026 की तिमाही में उसका राजस्व 14 प्रतिशत बढ़कर 48,211 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. परिचालन लाभ में 15.4 प्रतिशत की इजाफा हुआ और यह 10,163 करोड़ रुपये दर्ज किया गया. कंपनी की प्रति शेयर आय तिमाही के दौरान 19.19 रुपये रही. यह एक साल पहले की तुलना में 14.9 प्रतिशत अधिक है. तिमाही के दौरान कर्मचारियों की संख्या में 532 की कमी दर्ज की गयी. यह 31 मार्च 2026 के 3,28,594 से घटकर 30 जून को 3,28,062 रह गयी. तिमाही में कुल राजस्व में वित्तीय सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 27.9 प्रतिशत रही. विनिर्माण 15.9 प्रतिशत के साथ दूसरे और ऊर्जा, यूटिलिटी, संसाधन एवं सेवा क्षेत्र 13.4 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर रहा.

आशीष कुमार सीईओ नामित

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की अग्रणी कंपनी इंफोसिस ने आशीष कुमार दास को नामित मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है. वह अगले साल अप्रैल से पांच साल के लिए कंपनी के सीईओ एवं प्रबंध निदेशक बनेंगे. इंफोसिस के निदेशकमंडल की बैठक में उनकी नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की गयी. कंपनी ने बताया कि श्री दास 23 जुलाई से कंपनी के नामित सीईओ बनाये गये हैं.

शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 29 से

नई दिल्ली. जैव ऊर्जा पर वैश्विक प्रदर्शनी एवं शिखर सम्मेलन % बायोएनर्जी ग्लोबल-2026 इसी माह 29 से 31 तारीख राजधानी के यशोभूमि स्थित अंतराष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र में आयोजित किया जाएगा. बायोएनर्जी क्षेत्र पर देश के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की आयोजक मीरा ट्रेड फेयर मीडिया प्रा लि ने गुरुवार को एक विज्ञप्ति में बताया कि कार्यक्रम का उद्घाटन 29 जुलाई को सुबह 10ः30 बजे केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल करेंगे.

मध्य पूर्व तनाव से शेयर बाजार लुढ़का

नई दिल्ली, 23 जुलाई. भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत गुरुवार को लाल निशान में हुई. सुबह 9:21 पर सेंसेक्स 208 अंक या 0.27 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 76,553 और निफ्टी 51 अंक या 0.22 प्रतिशत की गिरावट के साथ 23,941 पर था.

शुरुआती कारोबार में फार्मा शेयरों में गिरावट बनी हुई है और निफ्टी फार्मा 0.81 प्रतिशत की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा था. इसकी वजह अमेरिकी टैरिफ के ऐलान को माना जा रहा है. इसके अलावा सूचकांकों में निफ्टी रियल्टी, निफ्टी आईटी, निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी सर्विसेज, निफ्टी प्राइवेट बैंक, लाल निशान में थे.

समाचार विशेष

एनडीए में फूट या अखिलेश के खिलाफ घेराबंदी!

लखनऊ. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास पासवान) के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने राज्य की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है.

सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं उनकी पार्टी उत्तराखंड और पंजाब चुनाव को लेकर भी अपनी रणनीतियां बनाने में जुटी है. बिहार के हाजीपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री और एलजेपी.आर प्रमुख ने खुद इस बात की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे. यूपी में चुनाव लड़ने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि जब में उत्तर प्रदेश में पंडित से लेकर पासवान की बात करता हूंए तो यह वह ब्रैकेट है जिसके बीच हर जातिए धर्म और समुदाय के लोग समाहित होते हैं. यूपी में एनडीए से अलग चुनाव लड़ने के चिराग पासवान के फैसले पर कई सवाल उठ रहे हैं. क्या एनडीए में फूट की चिंगारी तेज हो गई है या यह अखिलेश यादव के पीडीए वोटरों को तोड़ने की कोई रणनीति.

चिराग पासवान ने अपने बयान में कहा कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है. बिहार, झारखंड और नागालैंड के बाद अब अपने संगठन का विस्तार उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे राज्यों में करने जा रही है. कुछ समय पहले लखनऊ की सड़कों पर पार्टी की ओर से पोस्टर भी लगाए गए थे, जिस पर लिखा था. क्यों मांगे उधार अब अपना नेता तैयार. चिराग पासवान के इस कदम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है.

अखिलेश यादव के खिलाफघेराबंदी

इस फैसले को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफएक रणनीतिक घेराबंदी के तौर पर भी देखा जा रहा है. लोकसभा चुनाव में विपक्ष (सपा-कांग्रेस) ने संविधान और आरक्षण खतरे में है का नैरेटिव चलाकर दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा हासिल किया था. चिराग पासवान सीधे तौर पर विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं कि उन्होंने दलितों को भ्रमित कर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया. एक युवा दलित चेहरे के रूप में चिराग यूपी में उतरकर अखिलेश के इस नए दलित-पिछड़ा समीकरण को चुनौती देना चाहते हैं.

बिखराव की राजनीति से निकलेगी भाजपा की नैया!

क्या प्रशांत किशोर की पार्टी बनेगी एनडीए का विकल्प

पटना. बांकीपुर विधानसभा का चुनाव हमेशा रोचक रहा है. चुनाव में अंत अंत तक दोनों तरफ से रणनीति बनाई जाती है. पर होता यही आया है कि अब तक सीधी टक्कर की राह पर नितिन नवीन चुनावी जंग में जीत हासिल करते रहे हैं वह भी एक नहीं पांच पांच बार. पर इस बार बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रंग ही नहीं मिजाज भी अलग थलग है.

जनसुराज के नायक प्रशांत किशोर ने चुनाव में उतरकर चुनावी सेंसेशन बढ़ा दिया है. क्या क्या सनसनीखेज मसले हैं जिस पर चुनावी जीत हार के दाव पेंच लगाए जा रहे हैं. बांकीपुर के चुनावी रण में जनता भले यह मान रही है कि इस बार तगड़ा मुकाबला बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा और प्रशांत किशोर के बीच सीधी टकराहट है. पर बीजेपी के रणनीतिकारों की माने तो प्रशांत किशोर कहीं लड़ाई में ही नहीं है. मुकाबला तो राजद की रेखा गुप्ता से है. उधर राजद के रणनीतिकार भी खुद को बीजेपी के विरुद्ध सबसे कद्दावर उम्मीदवार बता रहे हैं. प्रशांत किशोर को तो राजद के नेता राजनीतिज्ञ मानते ही नहीं हैं. साथ ही जिस तरह से दल का अपना राजनीतिक आधार कोई खास दल होता है प्रशांत किशोर की पार्टी तो ऐसा दावा भी नहीं करती. राजनीतिक गलियारों की माने तो बीजेपी बांकीपुर चुनाव को त्रिकोणात्मक संघर्ष के रस्ते उतारना चाहती हैं. साथ में दूसरे नंबर पर राजद की वकालत भी करती है.

पीके कहीं नहीं : एजाज- राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद कहते भी हैं कि राजद आधी आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहा है. महिलाएं यहां ठगी गई हैं. ऐसी महिलाओं का रेखा गुप्ता प्रतिनिधित्व कर रही हैं. बांकीपुर की जनता इस बात का भी प्रतिकार कर रही है कि किसी को खड़ा करवा के बीजेपी कैसे जीत हासिल करती है.

एनडीए का विकल्प बनने की कोशिश

प्रशांत किशोर की राजनीति प्रशांत किशोर की राजनीति का सूत्र वाक्य एनडीए का विकल्प बनना है. बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत कुमार का उतरना भी यही संकेत देता है. वैसे भी प्रशांत किशोर इस चुनाव से यह संदेश देना चाहते हैं कि सम्राट सरकार एक असफल और व्यवस्था विरोधी सरकार है.

कांग्रेस की नजर उत्तराखंड पर

नई दिल्ली. यह सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि राहुल गांधी आखिर छात्रों से जुड़ा कार्यक्रम करने के लिए उत्तराखंड क्यों गए? इसका जवाब यह है कि कांग्रेस की पैनी नजर उत्तराखंड पर है, जहां अगले साल के शुरू में चुनाव होने वाला है.

कांग्रेस को लग रहा है कि अगले साल के शुरू में जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश को छोड़ कर उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में कांग्रेस के लिए बहुत अच्छी संभावना है. तभी राहुल गांधी ने छात्रों के मामले में राजस्थान के बाद दूसरा मुकाम उत्तराखंड के देहरादून को चुना. इसका असर भी दिखा. जिस दिन राहुल का कार्यक्रम था उस दिन एक लोकप्रिय गायिका का कार्यक्रम उनके कार्यक्रम स्थल के बगल में ही रखा गया था लेकिन उस गायिका के कार्यक्रम से ज्यादा युवा राहुल गांधी के कार्यक्रम में जुटे. राहुल का छात्रों की गूंज कार्यक्रम बहुत सफल हुआ. ध्यान रहे राहुल गांधी का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश और बिहार जाने का था. नीट यूजी के पेपर लीक होने और परीक्षा रद्द होने के बाद कांग्रेस ने जो योजना बनाई थी उसके मुताबिक राहुल 17 जून को राजस्थान के कोटा गए.

विशेष | **भाजपा ने कर लिया जुगाड़, संसद में इस बार पास होगा परिसीमन बिल?**

टीएमसी के टूटने का भी नहीं हुआ फायदा!

नई दिल्ली. संसद के मानसून सत्र में इस बार सरकार कई बड़े और महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने की तैयारी में है. 20 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त तक चलेगा. करीब चार सप्ताह चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी. इस दौरान सरकार कई अहम बिल संसद में पेश कर सकती है.

इस बार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता परिसीमन विधेयक को पारित कराना है. इसके साथ ही महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक को भी आगे बढ़ाने की तैयारी है. सरकार चाहती है कि इन दोनों बड़े विधेयकों को इस सत्र में मंजूरी मिल जाए. संविधान संशोधन वाले विधेयकों को पारित कराने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत जरूरी होता है. फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के पास इतनी संख्या नहीं है. इसी वजह से सरकार उन दलों और सांसदों से समर्थन जुटाने की कोशिश कर रही है जो विपक्षी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं हैं. हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना (यूबीटी) के कुछ बागी सांसदों ने एनडीए का समर्थन करने का संकेत दिया है. इसके अलावा बीजू जनता दल के कुछ राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे और अन्य राजनीतिक बदलावों से सरकार की स्थिति पहले से मजबूत मानी जा रही है. जानकारी के मुताबिक, सरकार अब एम के स्टालिन की द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम का समर्थन हासिल करने की कोशिश में भी लगी है, जो तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस द्वारा गठबंधन तोड़कर सी जोसेफ विजय के तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन देने से कांग्रेस से नाराज चल रही है. माना जा रहा है कि अगर डीएमके और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल साथ आते हैं तो सरकार के लिए जरूरी बहुमत जुटाना आसान हो सकता है. इसी वजह से लगातार राजनीतिक बातचीत जारी है.

सरकार पिछले बजट सत्र में जरूरी संख्या बल नहीं जुटा सकी थी. इसके कारण महत्वपूर्ण संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया. यह मोदी सरकार के लिए बड़ा झटका माना गया क्योंकि लंबे समय बाद सरकार का कोई महत्वपूर्ण विधेयक संसद में पास नहीं हो सका था.

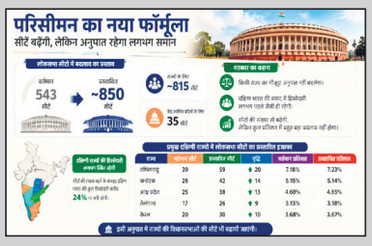

परिसीमन को लेकर नया फॉर्मूला तैयार

सरकार ने परिसीमन को लेकर नया फॉर्मूला तैयार किया है. इसके तहत लोकसभा की कुल सीटें 543 से बढ़ाकर करीब 850 करने का प्रस्ताव है. इनमें लगभग 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी. सरकार का कहना है कि इससे किसी राज्य का मौजूदा अनुपात नहीं बदलेगा. सरकार ने साफ किया है कि नए परिसीमन के बाद भी दक्षिण भारत की संसद में हिस्सेदारी लगभग पहले जैसी ही रहेगी. यानी सीटों की संख्या तो बढ़ेगी, लेकिन कुल प्रतिशत में बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा. इससे दक्षिणी राज्यों की चिंता दूर करने की कोशिश की जा रही है.